दिल्ली, हिमाचल की हार से सतर्क भाजपा का गुरुग्राम में होगा मंथन

शनिवार से दो दिवसीय बैठक में पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और फिर सांसद-विधायकों की होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम व हिमाचल विधानसभा चुनाव में हार से सतर्क हरियाणा भाजपा गुरुग्राम में दो दिन मंथन के लिए जुटेगी। शनिवार से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों सहित सांसद व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मनोहरल लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का संबोधन रहेगा। केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह सहित केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव भी इस मंथन के दौरान उपस्थित रहेंगी।

इस दौरान जहां गुरुग्राम, फरीदाबाद व मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी वहीं पंचायत चुनाव में जीते जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराकर चेयरमैन व वाइसचेयरमैन पद पर आसीन होने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दौरान प्रदेश भाजपा की ओर से सेवा कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी भी पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि ओपी धनखड़ ने तीन माह का रोड मैप सांसद, विधायकों से लेकर प्रदेश व जिला पदाधिकारियों के लिए तैयार कर लिया है।

आयुर्वेदिक व एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की संयुक्त पढ़ाई, डिप्लोमा व डिग्रियां मिलेंगी

अनुराग अग्रवाल • चंडीगढ़

- योगा व फिजियोथैरेपी को भी साथ-साथ जोड़ने की तैयारी, संयुक्त पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे
- हरियाणा सरकार ने संयुक्त पाठ्यक्रम बनाने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया

देश में एलोपैथी और आयुर्वेदिक उपचार पर चल रही बहस के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अब राज्य में आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों चिकित्सा पद्धतियों में डाक्टरी की संयुक्त पढ़ाई कराएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। कोरोना काल में मरीजों के इलाज में जहां एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कारगर साबित हुई है, वहीं मुख्यमंत्री ने संयुक्त चिकित्सा पद्धति को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की पहल की है।

आयुष-एलोपैथी की संयुक्त पद्धति से इलाज के साथ-साथ योग व फिजियोथैरेपी को साथ-साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि किसी भी गंभीर और असाध्य बीमारियों में अंग्रेजी इलाज के साथ-साथ देसी इलाज काफी कारगर साबित होता है। हजारों ऐसे मरीज हैं, जो अंग्रेजी दवाई तो खाते ही हैं, लेकिन साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। योगा और फिजियोथैरेपी भी लगभग एक समान है। योगा किसी भी बीमारी के उपचार का प्राकृतिक रूप हो गया और फिजियोथैरेपी अंग्रेजी रूप हो गया। इसलिए राज्य सरकार अपने प्रदेश में ऐसी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिसमें गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को बढ़िया उपचार हासिल हो सके।

प्रदेश सरकार ने आयुष-एलोपैथी की संयुक्त पद्धति से इलाज के फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी संयुक्त पाठ्यक्रम के नियम, संयुक्त पाठ्यक्रम और इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए फैकल्टी की जरूरत का अध्ययन कर अगले साल 30 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। आयुष-एलोपैथी की संयुक्त चिकित्सा पद्धति के तहत राज्य सरकार ज्वाइंट- डिग्री/डिप्लोमा कोर्स इन आयुष-एलोपैथी कराएगी। साथ ही योगा विद फिजियोथैरेपी इंटीग्रेशन कोर्स होगा।

पांच अधिकारियों की यह कमेटी तैयार करेगी संयुक्त पाठ्यक्रम : हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त सचिव जी अनुपमा की ओर से संयुक्त फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें आयुष महानिदेशक, श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के वीसी के विशेषज्ञ प्रतिनिधि, पीजीआइ रोहतक के वीसी के विशेषज्ञ प्रतिनिधि, डा. निर्मल खंडेलवाल और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के संयुक्त निदेशक प्रशासन शामिल किए गए हैं। इस कमेटी को विस्तार से अपनी रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोर्स की अवधि, कोर्स की पढ़ाई के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकें, उनके लेखक और जरूरत पड़ने वाली फैकल्टी के बारे में कंपलीट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। फिर इस रिपोर्ट के साथ वित्त विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा करेंगे। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है।

अनिल विज कर चुके दोनों चिकित्सा पद्धतियों का समर्थन

बाबा रामदेव के बयानों के बाद आयुर्वेद व एलोपैथी पद्धति से इलाज की बहस के बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान आया था कि ऐसी बहसबाजी से मरीजों में भ्रम फैल सकता है, ये वक्त बहस का नहीं, बल्कि मरीजों की हौसला अफजाई करने व उनको बेहतर इलाज देने का है। जहां आयुर्वेद से इलाज हो, वहां इससे हो सकता है, जहां एलोपैथी की जरूरत हो, वहां उससे हो सकता है। सभी का अपना-अपना महत्व है। इस पर बेवजह बहस किया जाना ठीक नहीं है। इलाज की यह पद्धतियां एक-दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे की सहयोगी हैं।

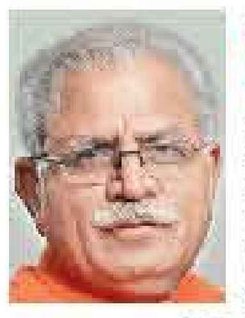

> एलोपैथी व आयुर्वेद दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां हमारा देश भारत में काफी प्रसिद्ध हैं। हालांकि अक्सर ये सवाल उठता है कि इन दोनों पैथी में से कौन-सी पैथी ज्यादा बेहतर है या फिर किस बीमारी के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जहां बीमारी से बचाव और उसको जड़ से खत्म करने में असरदार है, तो एलोपैथी एक्यूट और सीवियर बीमारियों, जटिल आपरेशन और इन्फेक्शन के इलाज में बेहतर है। दोनों ही पैथी के कुछ न कुछ लाभ हैं। कौन सी पैथी सही है या कौन सी सही नहीं है, इसकी बहस में पड़ने की बजाय हमारी सरकार संयुक्त चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करते हुए इसमें पढ़ाई कराने जा रही है, ताकि हमें दोनों का फायदा मिले।
>
> – **मनोहर लाल**, मुख्यमंत्री हरियाणा

एक नजर में

हटाकर दोबारा लगाए गए क्लर्कों को राहत

चंडीगढ़ : विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत भर्ती हुए लिपिकों, जिन्हें ज्वाइनिंग तिथि के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था तथा संशोधित परिणामों के उपरांत जिन्होंने उसी विभाग या अन्य विभाग में ज्वाइनिंग दी है, उनकी सेवा के बीच के समय को 'अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि' के रूप में माना जाएगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। राब्यू

महाविद्यालय शिक्षक संघ पहुंचा सीएम दरबार

चंडीगढ़ : हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष डा. अमित चौधरी ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू करते समय शिक्षकों से कोई सुझाव नहीं लिए गए। रेगुलेशन में यूजीसी द्वारा प्रदान की गई एमफिल/पीएचडी इंक्रीमेंटस को शामिल नहीं करना, सेवानिवृत्ति आयु न बढ़ाना एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति देना शिक्षकों के हितों की घोर अनदेखी है।“ ग्रामीण सेवा की बाध्यता के कारण शिक्षकों के सीनियर स्केल, सेलेक्शन ग्रेड एवं पे-बैंड-4 विभाग द्वारा रोक लिए गए हैं। राब्यू

किसानों पर न थोपें नैनो यूरिया : अभय चौटाला

चंडीगढ़ : इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों को नैनो यूरिया (लिक्विड) जबरदस्ती देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से पांच बैग यूरिया खरीदने पर आधा लीटर नैनो यूरिया खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। अगर किसान नैनो यूरिया खरीदने से इन्कार करता है तो उसे यूरिया नहीं दिया जाता। हालत यह है कि किसान को अपनी फसल के लिए अगर पांच बैग से ज्यादा यूरिया की जरूरत है तो वह तीन या चार बैग ही खरीदने पर मजबूर है। अगर सरकार को लगता है कि नैनो यूरिया किसानों के लिए लाभदायक है तो पहले उन्हें इसके बारे में शिक्षित करे। अगर किसानों को लगेगा कि यह उनके लिए फायदेमंद है तो वह खुद ही नैनो यूरिया की मांग करेगा। राब्यू

सेवा में देरी मामले में क्लर्क पर 10 हजार जुर्माना

चंडीगढ़ : सरकारी सेवाओं में देरी के मामले में मंडी बोर्ड के एक क्लर्क पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रोहतक निवासी सविता की ओर से सेवा का अधिकार आयोग में स्वत: अपील दायर हुई थी। अपीलकर्ता ने पिछले साल दिसंबर में 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे यह कहते हुए लाभ नहीं दिया गया कि मामले में कुछ कानूनी कार्रवाई निहित है। आयोग ने जांच के बाद पाया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव द्वारा अतिरिक्त जिला अटार्नी को गलत तरीके से फाइल भेजी थी। मंडी बोर्ड के रोहतक कार्यालय में लिपिक गुरदीप ने फाइल को ढाई महीने तक लंबित रखा। उसे नोटिस जारी किया गया, परंतु वह उचित कारण नहीं बता सका। राब्यू

बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, बाल-बाल बची

करनाल : शिव कालोनी में घर की छत पर खेल रही नौ साल की बच्ची पर पड़ोसी के पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया। जैसे ही कुत्ते ने बच्ची पर हमला किया तो वह चीखने लगी। आवाज सुनकर स्वजनों ने उसे बचाया। बच्ची को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पड़ोसियों का कहना है कि इस कुत्ते का मालिक इसे बच्ची की ही गलती बता रहा है। इस घटना से लोगों में रोष है। जासं

29 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेंगे पीले राशन कार्ड

25 को सुशासन दिवस पर आनलाइन माध्यम से उपहार देंगे मुख्यमंत्री

लंबे समय से हरियाणा में नहीं बन पाए हैं राशन कार्ड, अब खत्म हो जाएगा पात्र लोगों का इंतजार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में पीले राशन कार्ड के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के करीब 29 लाख परिवारों के लिए राहत की खबर है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आनलाइन माध्यम से सभी लाभार्थियों को पीले राशन कार्ड जारी करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है।

प्रदेश में बीपीएल कार्डों को लेकर विवाद रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछली सरकारों में कराए गए बीपीएल सर्वे को रद कर नए सिरे से सर्वे करने के आदेश दिए थे। इसके बाद नागरिक सूचना संसाधन विभाग का गठन किया गया और बीपीएल परिवार के आंकड़ों का मिलान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से करवाया। इतना ही नहीं, बीपीएल कार्ड के लिए न्यूनतम वार्षिक आय को एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया। नतीजन बीपीएल लाभार्थियों की संख्या 11 लाख 50 हजार से बढ़कर सीधे 28 लाख 93 हजार पर पहुंच गई।

आनलाइन बनवा सकते राशन कार्ड : कोई भी व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरल पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को दो श्रेणियों अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार में विभाजित किया गया है। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और बीपीएल/ओपीएच परिवारों को पांच किलोग्राम अनाज दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा है। कोरोना काल के समय आरंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 से मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह अंत्योदय आहार योजना के अंतर्गत बीपीएल/एएवाई परिवारों को हर महीने दो लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए 250 रुपये खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। पांच जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकूला में फोर्टिफाइड आटा दिया जा रहा है।

नौ लाख से अधिक गरीब परिवारों को मिले रसोई गैस कनेक्शन

वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार 1600 रुपये की मदद देती है। केंद्र की ओर से सात लाख 31 हजार परिवारों को, जबकि स्टेट फंड से एक लाख 88 हजार से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। इस तरह से हरियाणा में नौ लाख 19 हजार गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों से जुड़ेंगे स्कूली विद्यार्थी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक यह कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की सभी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जा रहा है। सरकार पीपीपी के आधार पर 37 लाख फर्जी ट्रांजेक्शन पकड़ चुकी है। करीब 150 योजनाओं में ये लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। अपात्र लोगों के योजना से बाहर होने पर हरियाणा सरकार के 1,200 करोड़ रुपये की बचत होने का दावा किया है। पीपीपी पोर्टल पर लगभग 70 लाख परिवारों और 2.60 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हो चुका है। राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी पीपीपी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को पीपीपी से लिंक किए जाने आदेश के बाद शुक्रवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की है।

बोर्ड एवं निगमों में काम करने वाले 70 हजार कर्मचारियों को बोनस संभव

- न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए राज्य स्तरीय मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड का गठन जल्दी
- भारतीय मजदूर संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की श्रमायुक्त सुजान सिंह से हुई लंबी वार्ता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के बोर्ड एवं निगमों में काम करने वाले करीब 70 हजार कर्मचारियों को पिछले तीन साल का बकाया बोनस किसी भी समय मिल सकता है। भारतीय मजदूर संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में राज्य के श्रम आयुक्त सुजान सिंह यादव ने कर्मचारियों का बकाया बोनस जल्दी दिलाने का भरोसा दिलाया है। कर्मचारियों को उनके वेतन पर 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस मिलता है। लगातार दो साल कोरोना की वजह से तथा एक बार विभागीय लापरवाही की वजह से कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल पाया है।

भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री पवन कुमार के नेतृत्व में राज्य श्रमायुक्त सुजान सिंह से मिले प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक श्रमिकों, मजदूरों व कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान गोदारा एवं प्रदेश महामंत्री हवा सिंह ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारण नए सिरे से नहीं हो पाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि साल 2020 में न्यूनतम वेतन निर्धारण होना था, जो दो साल से लंबित है। इसलिए सलाहकार समिति का गठन तत्काल किया जाना चाहिए। संगठन मंत्री पवन कुमार ने कहा कि वर्तमान में 21 हजार की वेतन सीमा के कारण श्रम कल्याण बोर्ड की सुविधाओं का लाभ श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। इसलिए तत्काल एडवाइजरी बोर्ड का गठन होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार व कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान गोदारा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मेडिकल पालिसी बनाने की मांग रखी। बातचीत में संयुक्त श्रम आयुक्त मुख्यालय परमजीत सिंह, फैक्ट्री विंग के एडीशनल डायरेक्टर अरविंद गुप्ता शामिल हुए।

सीधे हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती जमानत याचिका

एससी-एसटी एक्ट मामला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सीधे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। करनाल निवासी विनोद बिंदल ने हाईकोर्ट को बताया कि वह पत्रकार है और पुलिस व मार्केटिंग बोर्ड को लेकर खबरें लिखता आ रहा है। इन खबरों के कारण ही उसे झूठे मामले में फंसा कर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी गई है। 19 अक्टूबर को उस पर दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट का प्रविधान है। याची को पहले वहां जाना चाहिए था। याची ने सीधा हाईकोर्ट को रुख किया, जो गलत है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दे दी।

सार्वजनिक सूचना

लोकायुक्त, हरियाणा चंडीगढ़ के ऑफिस में ज्वाईंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति

इस समाचार पत्र में दिनांक 22.11.2022 को प्रकाशित रिटायर डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज/एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज से चंडीगढ़ में लोकायुक्त, हरियाणा के ऑफिस में ज्वाईंट रजिस्ट्रार के एक पद हेतु पूर्व सूचना की निरंतरता में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 02.01.2023 को सायं 5.00 बजे तक विस्तारित की गई है।

अवर सचिव
कार्यालय लोकायुक्त,
हरियाणा

PRDH-1244/11/4/2023/14408/67/4

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	एचएसआईआईडीसी	टर्नकी आधार पर बहादुरगढ़ सेक्टर-16 (हरियाणा) में 2×12.5 एमवीए, 33, 11 केवी इंडोर सब स्टेशन हेतु डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमशनिंग	19.12.2022 09.01.2023	7.12 CRORES	https://etenders.hry.nic.in	se.electrical@hsiidc.org.in

PRDH-13/2023/40/14415/I/67/4 आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय अधिशासी अभियंता (SDW)-VI
वेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (WSTP), केशोपुर आउटर रिंग रोड,
नई दिल्ली-110018, ई-मेल : eesdw06@gmail.com
कोरोना को रोकें, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें

प्रेस निट सं.- 19 (2022-23)/EE (SDW) VI (Re-Invited)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन में निविदा जारी की तिथि	ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय
1.	11 वर्ष व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण सहित केशोपुर एसटीपी फेज की 12 एमजीडी से 18 एमजीडी तक क्षमता संवर्धन एवं अपग्रेडेशन।	1,77,21,17,500/-	1.78 करोड़	1500/-	2022_DJB_233110_1 दिनांक 15.12.2022	10.01.2023 को अप. 03.00 बजे

इस सम्बंध में और अधिक विवरण (https://govtprocurement.delhi.gov.in) पर देखा जा सकता है।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी, (सुनिल दीक्षित)
वि.सं.ज.सं.वि. 415 (2022-23) EE(SDW)VI

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मुख्य अभियंता (SDW)-NW, मार्फत अधिशासी अभियंता (CIVIL) SDW-NW
6वां तल, वरुणालय, फेस-II, करोल बाग, दिल्ली-110005, ई-मेल : eecsdwnw@gmail.com
"कोरोना को रोकें : मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनायें रखें"

प्रेस निट सं. 37 (22-23), EE(C)SDW-NW

प. सं.	कार्य का नाम	निविदा में अंकित राशि (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा शुल्क (रु. में)	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में निविदा जारी की तिथि	ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	सेक्टर 16डी एसपीएस द्वारिका में मौजूदा पत्थर की बाउंड्री वाल की मरम्मत एवं उत्थापन। निविदा आईडी 2022 DJB 233117 1	47,37,443/-	95,000/-	500/-	15.12.2022	28.12.2022 अप. 03.00 बजे तक

इस संबंध में अधिक विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी (अनिल कुमार शर्मा)
नि.सं.ज.सं.नि. 413 (2022-23) अधिशासी अभियंता (Civil) SDW-NW

"कोरोना को रोकें : मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनाये रखें"
दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (M)-1, अधिशासी अभियन्ता (T)-1,
एम-16, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेस-II, दिल्ली-110091, फोन नं.-011-22727815, ईमेल आईडी: eeeast1djb@gmail.com

प्रेस निविदा सूचना, निट सं. 38 (2022-23)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित अनुबंध कीमत (ईसीवी)/ निविदा में रखी राशि	धरोहर राशि (ईएमडी)	निविदा शुल्क	ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन में निविदा जारी की तिथि एवं निविदा आई.डी.सं.	ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	एईई एम 58 के तहत गणेश नगर I से मधुबन चौक एसी 58 में एचडीडी प्रणाली द्वारा मुख्य समांतर सीवर लाइन प्रतिस्थापना/ बिछाना। (पुन: आमंत्रित)	2,95,46,716.00	5,91,000.00	1500.00	14.12.2022 2022_DJB_233022_1	29.12.2022 को अप. 03.15 बजे
2.	एसी-58 में [illegible] गणेश नगर से गणेश चौक तक एचडीडी प्रणाली द्वारा मुख्य समांतर सीवर लाइन का प्रतिस्थापन। (पुन: आमंत्रित)	2,24,60,013.00	4,49,300.00	1500.00	14.12.2022 2022_DJB_233022_2	29.12.2022 को अप. 03.15 बजे

इस संबंध में अधिक विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी (मदन सिंह)
वि.सं.ज.सं.वि. 414 (2022-23) अधिशासी अभियंता (T)-1

यूको बैंक सम्मान आपके विश्वास का UCO BANK HONOURS YOUR TRUST

परिसर की आवश्यकता

बैंक उस परिसर को किराए पर लेना चाहता है जो अधिमानत: भूतल पर हो अथवा मॉल, शोपिंग सेंटर में प्रथम तल पर हो, तो वहां लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

बैंक को अपनी शाखा खोलने के लिए निम्नानुसार परिसर की आवश्यकता है : पंचकुला (सैक्टर -20,21, नजदीकी क्षेत्र- कार्पेट एरिया 1000 -1200 वर्ग फुट)

विस्तृत जानकारी 1. यूको बैंक, अंचल कार्यालय करनाल, (नजदीक पुराना बस स्टैंड) तथा 2. यूको बैंक, पंचकुला शाखा (सेक्टर 8) से प्राप्त की जा सकती है अथवा हमारे बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com से डाउनलोड की जा सकती है। मुहरबंद लिफाफे में निर्धारित फार्मेट में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07.01.2023 है।

फोन नं. 0184-4020151 अंचल प्रबंधक

पंजाब सरकार

निविदा/आरएफपी संदर्भ सं. सरहिंद 2022/08

नगर परिषद विभाग सरहिंद-फतेहगढ़ साहिब निम्न के लिए ऑनलाईन बोलियां आमंत्रित करता है।

सिविल कार्य :-
उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिए विनिआसू का संदर्भ लें।
कार्यों के लिए समापन तिथि : 29.12.2022 को समय 17.00 बजे
विवरण के लिए लॉग ऑन करें : http://eproc.punjab.gov.in/nicgep/app
नोट : निविदा/आरएफपी सूचना को कोई शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

कार्यकारी अधिकारी
एम.सी. सरहिंद एफजीएस
Ro No. : NA/12/13338/2022/19595

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, चरखी दादरी

शुद्धिपत्र

सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा दिनांक 14.12.2022 को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अनुबंध आधार पर एक पद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर-आर.बी.एस.के. की भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है। यह पद अनुसूचित जाति (पुरुष) के लिए आरक्षण है। आरक्षित पालिसी के तहत ही आरक्षित पदों को अधिकतम उम्र में छूट भी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26.12.2022 (सायं 4.00 बजे) रखी गई है। अन्य जानकारी के लिए कैंडिडेट्स www.nhmharyana.gov.in पर विजिट करें।

दिनांक : 16.12.2022
उप सिविल सर्जन (एन.एच.एम.)
कार्यालय सिविल सर्जन, चरखी दादरी
PRDH-1058/11/425/2023/14424/67/4 दूरभाष : 01250-221333

फोन नं. 0161-2857309
कार्यालय नगर पंचायत मलौद
जिला लुधियाना
npmaloudh@ymail.com
पब्लिक नोटिस

इस पब्लिक नोटिस से हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मलौद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत व सरकार की हिदायतों अनुसार अब मलौद शहर को GFC 1 स्टार रेटिंग घोषित किया जाना है। इसलिए इस पब्लिक नोटिस से आम पब्लिक को सूचित किया जाता है कि शहर को GFC 1 स्टार रेटिंग घोषित करने संबंधी यदि किसी व्यक्ति को कोई एतराज/सुझाव इश्तिहार प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर-अंदर लिखित रूप में दफ्तर नगर पंचायत मलौद में दे सकता है। अवधि पूरी होने के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी एतराज/सुझाव पर विचार नही किया जाएगा व शहर को GFC 1 स्टार रेटिंग घोषित करने के लिए आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कार्यसाधक अफसर
नगर पंचायत मलौद
R.No. NA/12/13322/2022/19561

पब्लिक नोटिस

इस पब्लिक नोटिस द्वारा हर आम और खास को सूचित किया जाता है कि नगर कौंसिल रुपनगर को स्वच्छ सर्वेक्ष2023 में भाग लेने के लिए कारवाई पूरी करने के लिए रुपनगर शहिर को जी.एफ.सी (गारवेज फ्री सिटी) और वाटर + घोषित किया जाना है। दफ्तर नगर कौंसिल द्वारा हाउस मीटिंग में मता नं. 149 तिथि 29.11.2022 जी.एफ.सी. (गारवेज फ्री सिटी) और वाटर + घोषित करने के लिए मता डाला गया है। भारत सरकार द्वारा जी.एफ.सी के लिए निर्धारित दर्जाबंदी 1, 3, 5, 7 स्टार द्वारा नगर कौंसिल रुपनगर द्वारा 3 जी.एफ.सी 3 स्टार के लिए भाग लिया जाएगा। इस लई स्वच्छा सर्वेक्ष के लिए रुपनगर शहर को जी.एफ.सी 3 स्टार घोषित करने और वाटर + के लिए आम पब्लिक से एतराज/ सुझाव प्राप्त करने संबंधी अगर किसी व्यक्ति को कई एतराज/ सुझाव हो तो वह अपना एतराज/ सुझाव विज्ञापन प्रकाशित होने से 15 दिनो के अंदर-अंदर लिखती रूप में दफ्तर नगर कौंसिल रुपनगर में दे सकता है। दिए समय के पश्चत प्राप्त होने वाले किसी भी एतराज/ सुझाव पर विचार नही किया जाएगा और शहर को जी.एफ.सी. (गारवेज फ्री सिटी) और वाटर + घोषित करने के लिए अगली कारवाई अमल में लाई जाएगी।

Executive Officer
Municipal Council
Rupnagar
R.No. NA/12/13363/2022/19620

पंजाब सरकार

निविदा सूचना संदर्भ सं. : ई-निविदा-एमई/एएमई/8/2022

नगर परिषद विभाग कार्यालय श्री मुक्तसर साहिब निम्नलिखित के लिए ऑनलाईन बोलियां आमंत्रित करते हैं :-

क्र. सं.	वस्तु	मात्रा लाखों में
1.	सरकार से अनुमोदित सूचिबद्ध फर्मो/ठेकेदारों/एल व सी समितियों/श्रम शक्ति आपूतिकर्ताओं से सिविल कार्य, श्रम शक्ति, रखरखाव ऑफिस वेबसाईट और अन्य कार्य, अन्य विस्तृत नियम व शर्तें किसी कार्यदिवस पर नगर परिषद, श्री मुक्तसर साहिब के कार्यालय या ई-निविदा वेबसाइट पर देख सकते हैं।	94.50

समापन तिथि व समय : 30.12.2022 को सायं 5.00 बजे तक।
विवरण के लिए लॉगऑन करें https://www.eproc.punjab.gov.in
नोट :- निविदा सूचना का कोई शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

हस्ता/- अध्यक्ष नगर परिषद श्री मुक्तसर सहिब
हस्ता/- कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद श्री मुक्तसर सहिब
हस्ता/- नगर अभियंता नगर परिषद श्री मुक्तसर सहिब
Ro No. : NA/12/10863/2021/19557

हरियाणा सरकार शुद्धिपत्र

क्र. सं.	बोर्ड निगम/ प्राधिकरण का नाम	पुरानी संदर्भ/निआसू सं.	शुद्धिपत्र की प्रकृति	बोर्ड निगम/ प्राधिकृत की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ईमेल
1	यूएचबीवीएन	NIT-02/ XENOPKKR/2022-23	SEALED TENDERS ARE INVITED FROM THE CONTRACTORS HAVING MINIMUM EXPERIENCE OF 2 YEARS AND SATISFACTORY PERFORMANCE CERTIFICATE FROM THE GOVT/PVT. ORGANIZATION FOR RUNNING OF CANTEEN THEY EARLIER WORKED FOR THE WORK: -RUNNING OF OFFICE CANTEEN OF UHBVN VIDYUT SADAN SECTOR-8, UHBVN KURUKSHETRA TO BE OPENED ON 22.12.2022 AT 03.30 PM.	www.uhbvn.org.in	9315467364 xenopkurukshetra@uhbvn.org.in
2	यूएचबीवीएन	NIT NO 31/2022-23	THE RECEIPT AND OPENING OF TENDER ENQUIRY NIT NO. 31/2022-23 FOR FOR CLEANING AND SWEEPING IN THE OFFICE BUILDING COMPOUND AND SURFACE AREA (OP) SUB DIVN., WEST AND 11 KV SWITCH HOUSE GHASS MANDI, AMBALA CITY - AGAINST NIT NO.31/2022-23 IS NOW FURTHER EXTENDED TO 28.12.2022.	www.uhbvn.org.in	01712540151 xenopambalacity@uhbvn.org.in
3	यूएचबीवीएन	NIT NO 30/2022-23 DATED 12.09.2022	THE RECEIPT AND OPENING OF TENDER ENQUIRY NIT NO. 30/2022-23 DATED 12.09.2022 FOR HIRING OF 1 NO. COMPLAINT VEHICLE (I.E. MAHINDRA/TATA FORCE/ANY OTHER JEEP OPEN FROM BACK SIDE) FOR THE OFFICE OF SDO(OP) SUB DIVN., UHBVN, EAST, AMBALA CITY EXTENDED TO 08.12.2022	www.uhbvn.org.in	01712540151 xenopambalacity@uhbvn.org.in
4.	यूएचबीवीएन	NIT NO 29/2022-23 DATED 16.08.2022	THE RECEIPT AND OPENING OF TENDER ENQUIRY NIT NO. 29/2022-23 DATED 16.08.2022 FOR HIRING OF 1 NO. COMPLAINT VEHICLE (I.E. MAHINDRA/TATA FORCE/ANY OTHER JEEP OPEN FROM BACK SIDE) FOR THE OFFICE OF SDO(OP) SUB DIVN., UHBVN, MODEL TOWN, AMBALA CITY IS NOW EXTENDED TO 27.12.2022	www.uhbvn.org.in	01712540151 xenopambalacity@uhbvn.org.in

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in PRDH- 13/2023/80/14426/I/67/4

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा
कौशल भवन, सेक्टर 3, पंचकूला

उद्यमी युवा-सम्मानित हुआ

हरियाणा राज्य में स्थित राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं में स्वरोजगार स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सफल उद्यमियों को पुरस्कृत करने की योजना लागू की है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में गणतंत्र दिवस समारोह 26.01.2023 के अवसर पर अपना सफल उद्यम स्थापित करने एवं चलाने में प्रथम विजेता उम्मीदवार को 10,000/- रुपए द्वितीय विजेता उम्मीदवार को 7,500- रुपए और तृतीय विजेता उम्मीदवार को 5,000/- की नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इन सभी पुरस्कृत उद्यमियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन उम्मीदवारों को राज्य स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस समारोह के अवसर पर प्रथम विजेता उम्मीदवार को 50,000 रुपए द्वितीय विजेता उम्मीदवार को 40,000/- रुपए और तृतीय विजेता उम्मीदवार को 30,000/- रुपए की नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपने जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 31.12.2022 से पहले आवेदन जमा करवा सकता है। आवेदन प्रपत्र एवं योजना के नियम व शर्तें विभाग की वेबसाइट www.itiharyana.gov.in से डाउनलोड करें।

PDH-1065/11/62/2023/14419/67/4 निदेशक